Dr Kumari Manju
H.O.D. ECO.
R.N.C.

TOPIC

Changing Role of state in Mixed Economy
or
Changing Role of Govt in Economic Development!

विकासशील
प्रत्येक अच्छी अर्थव्यवस्थाएं एक मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के श्रेणी में आता है। मेरिज के अनुसार ... कल्याणकारी कार्यों तक ही सीमित रखना चाहते वे भी सरकार को पुलिस तथा कुछ ... मानवीय समाज को मिश्रित चाहते हैं स्वप्नलोक में रहते हैं एक कुशल तथा मानवीय ... की जरूरत है। दोनों के बिना एक अर्थव्यवस्था को दोनों आधार - सरकार तथा बाजार की ... एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश आधुनिक अर्थव्यवस्था के परिचालन का प्रयास एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करने के समान है" ["The good Mixed economy is perforce, the limited Mixed economy. But those who would reduce the Government to the constable plus a few light houses are living in a dream world. An efficient and humane society requires both halves of the Mixed system - Market and government. Operating a Modern economy without both is like trying to clap with one hand"]।

1945 से लेकर 1980 के दशक के शुरुआत के वर्षों में विकास की प्रचलित रणनीति को अपनाया गया उसे अंतर्मुखी तथा हस्तक्षेपकारी (inward looking and interventionist) कहा गया है। इस रणनीति के अन्तर्गत उन उद्योगों के विकास व उत्पादन पर बल दिया गया जिनके उत्पादों का उपभोग आयात किया जाता था इसलिए इसे आयात प्रतिस्थापन (import-substitution) की रणनीति भी कहा गया।

इस नीति के अन्तर्गत घरेलू उद्योगों को Tariff की दर को ऊँची करके संरक्षण प्रदान किया गया, साथ ही आयातों पर परिमाणात्मक या कोटा प्रतिबंध लगाया गया। प्रमुख उद्योगों के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को अहम भूमिका प्रदान की गई। भारत में योजना के प्रारंभिक अवधि में विकास के क्षेत्र में सरकार को प्रमुख अभिनेता की भूमिका प्रदान की गई। निजी विनियोग को कठोर नियंत्रण में रखा गया तथा सभी महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्रों को सौंपा गया। आयात को कठोर नियंत्रण में रखा गया तथा Tariff की दर काफी ऊँचा किया गया। राज्य की आर्थिक भूमिका में विस्तार के साथ-साथ लोक वित्त की भूमिका में विस्तार हुआ क्योंकि लोक वित्त - कर, लोक व्यय, लोक ऋण तथा गैर कर राजस्व - द्वारा ही सरकार अपनी आर्थिक नीति लागू करती है।

सरकार की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के अधिकार में अधिक वृद्धि हुई। इससे भ्रष्टाचार में अत्यधिक तेजी आई। सब्सिडी, लाइसेंस, तथा कोटा प्राप्त करने के लिए घूस का प्रचलन बढ़ा। फलस्वरूप अधिकांश साधनों का आवंटन उसे हुआ जिनके राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी न कि उसे जो इनका प्रयोग अधिक कुशलता तथा कार्यकुशलता से कर सकते थे।

नीतियों को अधिक प्रभावी करने तथा सार्वजनिक उद्योगों के विस्तार करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए कर राजस्व में वृद्धि के उपाय किए गए। प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा परोक्ष करों पर अधिक जोर दिया गया तथा सभी प्रकार की वस्तुओं - कच्ची सामग्री, अन्तवर्ती वस्तु तथा निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर लगाने का आधार में विस्तार किया गया तथा कर की दरों में बार-बार वृद्धि की गई। कर की ऊँची दरों के कारण कर चोरी में वृद्धि हुई तथा सभी प्रकार की वस्तुओं पर करों का कर लगाने के प्रपाती (Cascading) प्रभाव पड़ा। Tax structure में विकृति आ गई, और इस बावजूद भी लोक राजस्व में वृद्धि नहीं हो पायी तथा लोक व्यय में तेजी बढ़ोतरी फलतः राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा परिणाम स्वरूप सरकार ने इसकी पूर्ति के लिए ... नए नोट्स का प्रकाशन कर व्यवस्था का सहारा लिया। इसके अन्तर्गत सरकार ... नई मुद्रा का सृजन करके भुगतान ... केन्द्रीय बैंक को देती है ... इससे ...

तथा मुद्रास्फीति का प्रचलन होगा है। इस स्थिति में मुद्रा स्फीति एक बड़ी समस्या बन जाती है।

राज्य की भूमिका में वृद्धि तो हुई, लेकिन न तो पूर्णरूपेण केन्द्रीय योजना को अपनाया गया और न ही आर्थिक साधन पूर्णरूप से राज्य के अधिकार में आए। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण रहा। 1980 के दशक में चार महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण अन्तर्मुखी विकास मॉडल का पुनर्मूल्यांकन किया गया। (i) जिन विकासशील देशों ने इस मॉडल को अपनाया वहाँ आर्थिक विकास की दर कम रही। (ii) रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों ने राज्यीय हस्तक्षेप, नियंत्रण की रणनीति को अपनाया इन देशों में आर्थिक विकास की दर बाजार-अर्थव्यवस्था आधारित देशों की विकास दर की तुलना में बहुत कम रही। (iii) ताइवान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा हांगकांग ने बाजार आधारित नीति को अपनाया, इन देशों में विकास की दर में तेजी से वृद्धि हुई। (iv) विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण से इस विचार को बल मिला कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति के बिना कोई भी देश विश्व आर्थिक विकास में अपनी पूरी भूमिका नहीं निभा सकता है। इसलिए इस विकास के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में स्वीकार करना होगा।

उपर्युक्त कारणों से विकास नीति के सम्बन्ध में एक नई विचारधारा को मान्यता प्राप्त हुई। इसे बहिर्मुखी, विश्व-व्यापारोन्मुख, बाजार प्रेरणाओं पर आधारित विकास मार्ग (outward-looking, International-Trade-oriented, Market-Incentive based, Route to development) कहा गया है। इस नीति के प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: (1) साधनों के आवंटन के लिए बाजार कीमत यंत्र के रूप में स्वीकार करना, (2) सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्था का त्याग, (3) विस्तृत पैमाने पर नियमन (regulation) का त्याग, (4) प्रतिस्पर्धा की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार करना, तथा (5) एकाधिकारवादी संचार माध्यम या सरकारी नियंत्रण वाले निजी फर्मों या श्रम संघों या उद्योगों की भूमिका को कम करना होता है और या सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों की भूमिका घट जाती है। सरकार को किन

इस मॉडल में राज्य तथा लोक वित्त की भूमिका इस प्रकार है। दो प्रकार के क्रियाओं को करना चाहिए। इस ढाँचे के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं: (1) सम्पत्ति के अधिकार को स्पष्ट व्याख्या। (2) मनमाने ढंग से सम्पत्ति की जब्ती का न होना, (3) कानून और व्यवस्था कायम रखना, (4) उचित एवं सुगठित मौद्रिक व्यवस्था, (5) व्यक्ति को सम्पत्ति खरीदने, निवेश और बेचने आदि का मूल अधिकार प्राप्त होना, तथा संरचना (infrastructure) का प्रावधान ~~करना~~ करना।

(ii) स्वार्थों के संघर्ष के समाधान बाजार की असफलताओं को दूर करने तथा सामाजिक न्याय की स्वीकृत धारणा के अनुसार आय का पुनर्वितरण हेतु ~~राज्य को वहाँ~~ निजी क्षेत्र

भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना का कहना है कि भरोसा करने का यह अर्थ नहीं है कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिस्पर्धा एवं बाजार शक्तियों पर राज्य की कोई भूमिका नहीं है या उसकी भूमिका विकास के सन्दर्भ में कम हो गयी है। राज्य की भूमिका घटी नहीं है बल्कि बदल गई है। उन क्षेत्रों में जहाँ बाजार स्पर्धा तथा कार्य कुशल वित्तीय क्षेत्र के माध्यम से निवेश तथा उत्पादन के विषय में उचित निर्णय लिया जा सकता है वहाँ पर राज्य का नियंत्रण तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाले की भूमिका से रहना होगा। लेकिन ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ राज्य की भूमिका में विस्तार हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में एक विशेष क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक विकास जिसका सम्बन्ध स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय जल की व्यवस्था आदि मूल सेवाओं से है। दूसरा आर्थिक संरचना का क्षेत्र है, जैसे सड़क, विद्युत, बन्दरगाह, रेलवे, दूर संचार, नगरपालिका सेवाएं, आदि। इन क्षेत्रों में भी निजी निवेश का महत्व कम नहीं है इस संदर्भ में बदली योजना की भूमिका है, फिर भी राज्य का महत्व कम नहीं है। इस नीति को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण का कथन महत्वपूर्ण है: "राजनीति को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू का सम्बन्ध सरकार की भूमिका से है अब यह सामान्यतः स्वीकार किया

स्वीकार किया जाने लगा कि अतीत में सरकार ने अत्यधिक दायित्व को अपने ऊपर ले लिया था, जिससे सीमित वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमताओं पर बहुत भार पड़ा था तथा वैयक्तिक प्रेरणाओं का गला घोंट गया। सरकार की विस्तृत भूमिका उस समय जरूरी हो सकती है जब निजी क्षेत्र की क्षमता अविकसित स्थिति में होती है किन्तु इस प्रसंग में अब नाटकीय परिवर्तन हुआ है। भारत में अब शक्तिशाली एवं गतिशील निजी क्षेत्र का विकास हो चुका है। भविष्य में अब औद्योगिक विकास निजी क्षेत्र के कोष निवेश पर निर्भर करेगा तथा सरकार केवल विकास के लिए एक वातावरण प्रदान करता है।"

"इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास को प्रोत्साहित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है या न्यूनतम भूमिका है। इसके विपरीत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, किन्तु यह भूमिका अतीत की भूमिका से भिन्न है। ऐसे अनेक क्षेत्रों जहाँ निजी क्षेत्र प्रवेश करना नहीं चाहेगा जैसे सामाजिक क्षेत्र, infrastructure का विकास इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका का विस्तार होगा।"

फिशर तथा डॉर्नबुश का कहना है कि Changing Role of Govt में बाजार की केन्द्रीय भूमिका पर बल देता है तथा निजी क्षेत्र को विकास का इंजन मानता है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका यह है कि वह आर्थिक क्रियाओं के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करे। इस अनुकूल वातावरण के अन्तर्गत कानूनी, संस्थागत तथा नीतिगत ढाँचा आते हैं जो सरकार ऐसे वातावरण का निर्माण करती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान, सामाजिक सेवा और निर्धनता को दूर करने, मूल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, जैसे सामाजिक सुरक्षा, जैसे समष्टि आर्थिक स्थिरता तथा राजकोषीय व्यवस्था के क्षेत्र में है। यही लोक वित्त की बदलती भूमिका है। राजकोषीय नीति का उपयोग नियमन, नियंत्रण तथा हस्तक्षेप के लिए नहीं किया जाता है बल्कि निजी क्षेत्र के सुचारु संचालन के उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए होता है।

सैमुअलसन तथा नॉरडस के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार के निम्न तीन प्रमुख आर्थिक कार्य हैं:

(1) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रदूषण जैसी बाह्यताओं को नियंत्रित करके तथा लोकवस्तुओं का प्रावधान करके कार्यक्षमता में वृद्धि करना।

(2) विशेष वर्गों के पक्ष में कर तथा व्यय कार्यक्रमों के माध्यम से आय का पुनर्वितरण करके समानता (equity) को प्रोत्साहित करना।

(3) राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नियमन के माध्यम से समष्टि आर्थिक स्थायित्व तथा विकास को प्रोत्साहित करते हुए बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति को कम करना।

Scanned with CamScanner